

अधिकतम : 28° C
न्यूनतम : 24° C

खबरें छुपाता नहीं, छापता है

शाह टाइम्स

हल्द्वानी, शुक्रवार 1 अगस्त 2025 हल्द्वानी संस्करण: वर्ष 22 अंक 341 पृष्ठ 12 मूल्य रुपये 5.00

www.shahtimesnews.com

विस्तृत खबरों के लिए QR
कोड स्कैन करें।
मुफ्त पढ़ें E-paper

स्कूलों के विलय पर योगी सरकार का यूटर्न

पेज 2



ओवल टेस्ट: गिल ने तोड़ा गावस्कर का रिकॉर्ड

खेल टाइम्स

सियाम की परछायां: मंदिर, युद्ध और वैश्विक शतर्ज
सम्पादकीय

हो सकता है, भारत को तेल बेचे पाक: ट्रम्प

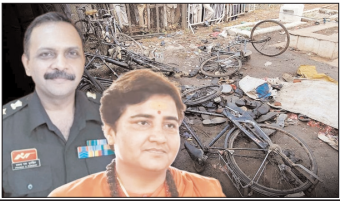
पेज 12

मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपी बरी

मुंबई, वार्ता

सितम्बर 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में गुरुवार को मुंबई की एक विशेष अदालत ने पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। इस विस्फोट में छह लोग मारे गए थे और 101 अन्य घायल हुए थे।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के मामलों की सुनवाई के लिए नियुक्त विशेष न्यायाधीश एके लाहोटी ने अभियोजन पक्ष के मामले और को गौरी गांव में कई खामियां



बताई। उन्होंने कहा कि आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। विस्फोट के सभी छह पीड़ितों के परिवारों को दो-दो लाख रुपये और सभी घायलों को 50-50 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। पीड़ित परिवारों के वकील एडवोकेट शाहिद नदीम

ने कहा कि बम विस्फोट की पुष्टि कोर्ट ने कर दी है। हम इस बरी करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। हम स्वतंत्र रूप से अपील दायर करेंगे। 29 सितम्बर 2008 को मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास एक

■ एनआईए कोर्ट का फैसला, विस्फोट में छह लोग मारे गए थे और 101 अन्य घायल हुए थे, कोई विश्वसनीय और ठोस सबूत नहीं

■ फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे पीड़ित परिवारों के वकील

मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट होने से छह लोगों की मौत हो गई थी। घमाके में 100 से अधिक घायल हुए थे। न्यायाधीश ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि मामले को संदेह से परे साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय और ठोस

सबूत नहीं है। मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधान लागू नहीं होते। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह साबित नहीं हुआ है कि विस्फोट में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर पंजीकृत थी, जैसा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया है। यह भी साबित नहीं हुआ है कि विस्फोट कथित तौर पर बाइक पर लगाए गए बम से हुआ था। अदालत ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। कोई भी धर्म हिंसा का समर्थन नहीं कर सकता। अदालत केवल धारणा और नैतिक-श्रेष्ठ पृष्ठ दो पर

लैंडस्लाइड से केदारनाथ यात्रा रुकी गाजियाबाद में सोसाइटी का बेसमेंट धंसा

नई दिल्ली। यूपी के गाजियाबाद में रात भर की बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो गया।

2500 लोग फंसे

क्रॉसिंग रिपब्लिक के पास सुरांगत एक्वापोलिस सोसाइटी का बेसमेंट करीब 15 फीट धंसा गया। बेसमेंट में खड़ी 4 गाड़ियां मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गईं।

दूसरी तरफ, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मुनकटिया के पास बुधवार को लैंडस्लाइड

दिल्ली-एनसीआर में मध्यम बारिश का अनुमान नई दिल्ली। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अगले दो दिन के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार लौनी देहात, हिंडन वायुसेना स्टेशन, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपरा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के इलाकों में बारिश का अनुमान है। सुबह न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा और दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। पिछले कई दिनों में राजधानी में हुई भारी बारिश से दिल्लीवासियों को अनेक स्थानों पर जलभराव और यातायात जाम की समस्या का सामना करना पड़ा।

हुई। इससे केदारनाथ जाने वाला पैदल रास्ता बंद हो गया, यात्रा 4 दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

सड़क के अचानक बंद होने से गौरीकुंड में लगभग 2,500 तीर्थयात्री फंस गए हैं।

लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित नई दिल्ली।

लोकसभा में विपक्षी दलों ने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले को लेकर गुरुवार को भारी हंगामा किया जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम विलास ने दो बार के स्थगन के बाद चार बजे तीसरी बार जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा और नारेबाजी करते हुए सदन के बीचोंबीच आ गए। हंगामे के बीच ही वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी टैरिफ पर संसद में बयान दिया और कहा कि भारत और अमेरिका के बीच वार्ता जारी है, लेकिन भारत अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा करेगा।

मुंबई एयरपोर्ट पर आठ करोड़ की ड्रम्स जल

मुंबई। मुंबई कस्टम डिपार्टमेंट के एक्विजिशन अधिकारियों ने 8 करोड़ रुपये की ड्रम्स जल की है। यह कार्रवाई 29 और 30 जुलाई को हुई। इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कस्टम ऑफिसर ने छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैंकोंक से आई फ्लाइट नंबर बीजी-760 से तीन सदिग्ध पैसेजर्स को रोका था। इनके सामान की जांच के दौरान 1.990 किग्रा गांजा मिला, जिसकी बाजार में करीब 2 करोड़ रुपये की कीमत है। मुंबई एयरपोर्ट के ही एक दूसरे मामले में बैंकोंक की फ्लाइट नंबर 6ई.1060 से एक पैसेंजर के पास 6.22 किग्रा गांजा बरामद किया। इसकी बाजार कीमत 6 करोड़ रुपये है।

सेना उप प्रमुख सुब्रमण्य सेवार्निवृत्त नई दिल्ली।

सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य 39 वर्ष की उल्लेखनीय सेवा के बाद गुरुवार को सेवानिवृत्त हो गए। सेना में उनकी विशिष्ट यात्रा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से शुरू हुई और दिसम्बर 1985 में उन्हें गढ़वाल राइफल में कमीशन दिया गया। असाधारण शैक्षणिक क्षमता वाले अधिकारी के रूप में उन्होंने किंग्स कॉलेज, लंदन से स्नातकोत्तर की डिग्री और मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा अध्ययन में एम.फिल की डिग्री प्राप्त की।

वाशिंगटन, वार्ता

भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत और रूस को डेड इकोनॉमी बताया। उन्होंने कहा कि भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ले डूबें, मुझे क्या। एक दिन पहले ट्रम्प ने भारत पर 1 अगस्त से 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। अभी अमेरिका की तरफ से भारतीय सामानों पर औसतन करीब 10 प्रतिशत टैरिफ लगता है। इसके बढ़ने से अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान के दाम बहुत बढ़ जाएंगे।

डेड इकोनॉमी उस स्थिति को कहते हैं जब किसी देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप हो जाए या बिल्कुल सुस्त पड़ जाए। इसमें व्यापार, उत्पादन, नौकरियां और लोगों की कमाई लगभग रुक सी जाती है। विकास रुक जाता है और लोग आर्थिक तंगी में फंस जाते हैं। डेड इकोनॉमी कोई आधिकारिक आर्थिक टर्म नहीं है। ये एक बोलचाल का शब्द है, इसलिए इसे मापने का कोई सटीक पैमाना भी नहीं है। हालांकि इसे समझने के लिए कुछ आर्थिक संकेतकों का इस्तेमाल किया जा सकता है—जैसे जीडीपी, महंगाई, बेरोजगारी दर और व्यापार घाटा। ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया टुथ सोशल पर 30 जुलाई को ऐलान किया कि भारतीय



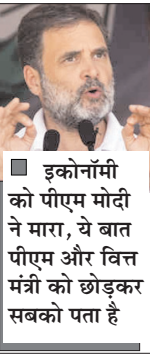
सामानों पर अमेरिका में 25 प्रतिशत टैरिफ लगेंगे। रूस से व्यापार के चलते भारत पर टैरिफ के अलावा पेनल्टी भी लगेगी। हालांकि ट्रम्प ने यह नहीं बताया कि पेनल्टी कितनी होगी। उन्होंने कहा कि 25 प्रतिशत टैरिफ और पेनल्टी दोनों 1 अगस्त, 2025 से लागू होंगे। ट्रम्प के 29 जुलाई को किए गए सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा था कि भारत हमारा दोस्त है, लेकिन हमने पिछले कई सालों में उनके साथ ज्यादा कारोबार नहीं किया, क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, शायद दुनिया में सबसे ज्यादा।

■ अमेरिकी राष्ट्रपति ने इंडिया को डेड इकोनॉमी बताया

■ कहा: मुझे क्या, आज से 25 प्रतिशत टैरिफ लगेगा

ट्रम्प ने सही कहा इंडियन इकोनॉमी मर चुकी: राहुल

नई दिल्ली। राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी (मृत अर्थव्यवस्था) बताने पर कहा—मुझे खुशी हुई कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने फैक्ट बताया है। राहुल ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि भाजपा ने अड़ानी की मदद के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। ट्रम्प सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री को छोड़कर सभी जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है।



■ इकोनॉमी को पीएम मोदी ने मारा, ये बात पीएम और वित्त मंत्री को छोड़कर सबको पता है

मोदी दोस्त बनाते हैं, बदले में क्या मिला, टैरिफ मुद्दे पर पीएम जवाब दें: प्रियंका

नई दिल्ली। संसद मानसून सत्र के 9वें दिन बिहार वोटर वेरिफिकेशन और अमेरिका के टैरिफ लगाने वाले मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। लोकसभा और राज्यसभा 3-3 बार स्थगित हुईं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को भारत पर 1 अगस्त से 25 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इस पर विपक्ष ने सदन और संसद के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ पर जो कहा उसे सबने देखा है। प्रधानमंत्री मोदी हर जगह जाते हैं, दोस्त बनाते हैं और फिर हमें बदले में यही मिलता है।

भारत-अरब अमीरात व्यापक रणनीतिक साझेदारी की मजबूती को प्रतिबद्ध

नई दिल्ली। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि पीएम मोदी ने बुधवार देर रात संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से टेलीफोन पर बात की। दोनों

■ पीएम मोदी ने शेख मोहम्मद बिन जायद से की फोन पर बात

नेताओं ने भारत और अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने प्रतिबद्धता दोहराते हुए द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति का सकारात्मक मूल्यांकन किया।

किसान संपदा का बजट 6,520 करोड़ हुआ

शाह टाइम्स ब्यूरो

नई दिल्ली। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना—(पीएमकेएसवाई) के लिए 1920 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कुल 6520 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी है।

सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की यहां हुई बैठक में

सरकार ने दी रेलवे की 11,169 करोड़ रुपये की चार परियोजनाओं को मंजूरी

नई दिल्ली। सरकार ने देश भर में आवागमन एवं माल परिवहन के बुनियादी ढांचे के विस्तार को गति देने के लिए गुरुवार को छह राज्यों में विभिन्न रेल खंडों पर अतिरिक्त लाइनों के निर्माण के लिए कुल 11,169 करोड़ रुपये की चार परियोजनाओं को मंजूरी दी।

इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि आज 15वें वित्त आयोग 2021-22 से 2025-26 की अवधि में चल रही पीएमकेएसवाई के लिए

1920 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय के साथ ही इस अवधि के लिए कुल 6520 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी गई है।

कबूतरों को दाना चुगाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट की रोक

मुंबई, वार्ता

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कबूतरों के झुंड को दाना डालना सार्वजनिक रूप से परेशानी पैदा करने वाला है। यह मुद्दा जन स्वास्थ्य से जुड़ा है और सभी उम्र के लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर और संभावित खतरा है।

जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डाक्टर की बेंच ने पशु प्रेमियों की दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मुंबई नगर निगम को दाना डालने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का भी निर्देश दिया। इसके



अलावा कोर्ट ने बीएमसी को शहर के कबूतरखानों में कबूतरों के जमावड़े को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने और कड़े उपाय लागू करने का निर्देश भी दिया। दरअसल, 3 जुलाई को इसी मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बीएमसी

■ कहा: यह सेहत के लिए भी खतरा

■ बीएमसी को दाना डालने वालों पर एफआईआर करने की परमिशन दी

का यह काम पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का उल्लंघन करता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अनुमति न मिलने के बावजूद लोग कबूतरखानों में कबूतरों को दाना डालना जारी रखे हुए हैं। अब यह स्थिति और भी जटिल हो गई है, क्योंकि पिछले आदेश में याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। नगर निगम के अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका जा रहा है। कानून की अवहेलना की जा रही है। हम बीएमसी को ऐसे किसी भी व्यक्ति और समूहों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देते हैं।

तेलंगाना में दलबदल विधायकों को SC का अल्टीमेटम

शाह टाइम्स ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में दलबदल करने वाले भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायकों की अयोग्यता पर तेजी से निर्णय लेने का निर्देश विधानसभा अध्यक्ष को दिया है।

कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यह फैसला तीन महीने के भीतर हो जाना चाहिए, वरना लोकतंत्र को नुकसान पहुंच सकता है। कोर्ट का यह आदेश तब आया है जब कांग्रेस में शामिल हुए 10 बीआरएस विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर सात महीने बाद भी कोई फैसला नहीं हुआ। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यदि स्पीकर समय पर कार्रवाई नहीं करते तो यह 'ऑपरेशन सफल, मरीज मृत' वाली स्थिति होगी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला 10वीं अनुसूची से जुड़ा है, जिसमें दलबदल की स्थिति में स्पीकर को त्वरित फैसला लेना होता है। कोर्ट ने स्पीकर से कहा कि वे विधायकों को



■ अदालत ने विधायकों की अयोग्यता पर तेजी से निर्णय लेने का निर्देश विधानसभा अध्यक्ष को दिया

प्रक्रिया में देरी नहीं करने दें और यदि ऐसा होता है, तो उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राजनीतिक दलबदल देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह पूरी प्रणाली को अस्थिर कर सकता है। कोर्ट ने संसद से भी आग्रह किया कि वह विचार करे कि क्या दलबदल मामलों में स्पीकर को ही निर्णय देने का मौजूदा तंत्र उचित है या इसमें बदलाव की जरूरत है।

जित किया गया। विद्यालय परिसरों में गैलरी, सहज, छिपन, बौटल ब्रैकेट के पौधे लगाए गए। राजनगरी एवं कंठार नगर में विद्यालय बच्चों के कक्षाओं में जाकर संवाद किया। अनुशासन, शिक्षा में रुचि और की सराहना की गई। अधिकारियों को जीवन में आगे बढ़ने, पर्यावरण तथा स्वच्छता को अपनी दिनचर्या के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कार्यकर्ता, स्वच्छता और शिक्षा के प्रदान के लिए हस्ताक्षर अभियान में राजनगरी छात्रों, शिक्षकों एवं अधिकारियों का योगदान किया।

नव-निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण

राज्य में बनेंगे एकीकृत पंचायत भवन: धामी

शाह टाइम्स संवाददाता
देहरादून। मुख्यमंत्री पर्यटन सिंह धामी ने गुरुवार को सविधानसभा में पंचायती राज विभाग को बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि नव-निर्वाचित ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्यों को आधुनिक तकनीकी, विधायी प्रबंधन और शासन प्रणाली पर प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकासित राष्ट्र बनाने के प्रथमस्रोत नरेंद्र मोदी के संकेत पर को पूर्ण करने की दिशा में सर्वोक्त समेकित प्रयास करने होंगे। गांवों के विकास से ही प्रदेश और देश का विकास संभव है।



■ 15 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होने का होगा आकलन

मुख्यमंत्री ने राज्य में 'एकीकृत पंचायत भवन' का निर्माण कराने के निर्देश दिए। इन एकीकृत

पंचायत भवनों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, पटवारी, आगा आदि के लिए एक स्थान पर ही व्यवस्था होगी। इनके बाद एक साथ बैठने के लिए रोस्टर भी बनाया जाए। इससे लोगों को सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों में बजट नियोजन को और बेहतर बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पंचायतीराज विभाग यह भी आकलन करे कि आगामी 15 वर्षों में कितना ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होगा। यह आकलन राज्य के समग्र विकास की

दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम सभाओं के स्थापना दिवस उत्सव के रूप में मनाया जाने के लिए ग्राम बावियों से संवाद किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत स्तर पर सभी योजनाओं की रीयल टाइम मॉनिटरिंग हो।

इस अवसर पर उपस्थित अनुभव प्राप्त परिषद प्राध्यापक विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आर. के. सुषोभा, आर. मीनाक्षी सुरेश, सचिव बंशीधर तिवारी व निदेशक पंचायती राज सुश्री निधि यादव उपस्थित थे।

...अब बिना पंजीकरण नहीं होगा मसूरी का दीदार!

होटल मालिकों को करना होगा पर्यटकों का पंजीकरण

शाह टाइम्स संवाददाता
देहरादून। अगर मसूरी के हिलकेश नगर और ठंडी वादियों में घूमने का सपना देख रहे हैं, तो जरा ध्यान दीजिए... अब बिना पंजीकरण के 'क्वीन ऑफ हिल्स' यानी पहाड़ों की रानी मसूरी को सैर करना आसान नहीं होगा।। अगस्त से पर्यटन विभाग ने एक नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है, जिसके तहत मसूरी आने पर अनिवार्य पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) करना होगा।

यार रहे यह ऑनलाइन पंजीकरण पर्यटकों को नही, बल्कि होटल और होमस्टे मालिकों को

पर्यटन विभाग के पोर्टल पर दर्ज करानी होगी जानकारी

देहरादून। पर्यटन विभाग के पोर्टल पर होटल और होमस्टे व्यवसायियों को अपने यहां रजिस्टर में पंजीकरण करने के बाद विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करे। खास बात ये है कि इस व्यवस्था से मसूरी में आने-जाने वाले लोगों का सटीक आंकड़ा मिल सकेगा, जिससे ट्रैफिक मैनेजमेंट, निदेशक गोपाल ने बताया कि घुसने आने वाले पर्यटकों को सही जानकारी

री रखने के लिये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के क्रम में पर्यटन विभाग ने एक रूपरेखा तैयार की है, जिसके तहत पर्यटकों का पंजीकरण करना होगा, जिसके लिये होटल और होमस्टे व्यवसायियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह अपने रजिस्टर में पंजीकरण करने के बाद विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करे। खास बात ये है कि इस व्यवस्था से मसूरी में आने-जाने वाले लोगों का सटीक आंकड़ा मिल सकेगा, जिससे ट्रैफिक मैनेजमेंट, निदेशक गोपाल ने बताया कि घुसने आने वाले पर्यटकों को सही जानकारी

पूरे राज्य में लागू हो सकता है मॉडल: गर्बाल
पर्यटन विभाग के सचिव धीराज गर्बाल ने बताया कि यह सिस्टम आने वाले समय में पूरे उत्तराखंड में लागू किया जा सकता है, खासकर उन जगहों पर जहां पर्यटकों का अत्यधिक दबाव रहता है। उनका साफ कहना है, हम किसी को मसूरी आने से रोक नहीं रहे, सब चाहते हैं कि पर्यटन सुव्यवस्थित और सतत विकास की राह पर आगे बढ़े। विभाग का मकसद है कि मसूरी में एक समय में कितने पर्यटक मौजूद हैं, इसका वास्तविक आकलन किया जा सके और निश्चित संख्या पर होने पर प्रवेश को नियंत्रित किया जा सके। हालांकि ऐसे पर्यटक जो मसूरी से होकर भारथांग जा रहे हैं, या फिर वह कुछ दूर के लिए ही घुसने आए हैं, उनके लिए पंजीकरण जरूरी नहीं है।

महाराज ने केन्द्रीय पंचायतीराज मंत्री से की शिष्टाचार भेंट

शाह टाइम्स संवाददाता
देहरादून। पंचायतीराज मंत्री सनातन महाराज ने राज्य में पंचायतीराज, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं देशी विकास मंत्री राजीव रजन सिंह (ललन सिंह) से उनके नई दिल्ली स्थित आवास पर शिष्टाचार भेंट कर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत उत्तराखंड को 193.84 करोड़ का आयोजन प्रदान करने पर उनका आभार जताया है।



भारत के पंचायतीराज मंत्री सनातन महाराज ने गुरुवार को केन्द्रीय पंचायतीराज, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं देशी विकास मंत्री राजीव रजन सिंह (ललन सिंह) से उनके नई दिल्ली स्थित आवास पर

शिष्टाचार भेंट कर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अधिनियम वर्ष 2025-26 के तहत कार्यालय समिति (एएससी) द्वारा संयोजित से 193.84 करोड़ धारा निर्धारण को कार्यकारी समिति (सीसी) पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आहुत बैठक में लागू शत-प्रतिशत रूप में सभी पटकों के साथ पारित किये जाने पर प्रदेश की जनता की



शाह टाइम्स संवाददाता
देहरादून। मुख्यमंत्री अनुरोध निःशुल्क गैस रफिल योजना के तहत लाभार्थियों को सिलेंडर भरने के लिए एनएलई डीपीटी के माध्यम से दी जाएगी। खास विभाग इसके लिए व्यवस्था बनाएगा कि इस धनराशि का उपयोग लाभार्थी केवल सिलेंडर भरने के लिए ही

अन्योदय निःशुल्क गैस रफिल योजना के लाभार्थियों के खाते में जाएगा पैसा

राज्य में 1 लाख 84 हजार काईधारक परिवार इस योजना से जुड़े

कर कर के राज्य में 1 लाख 84 हजार अन्योदय काईधारक परिवार इस योजना से जुड़े हैं, योजना का लाभ प्रदेश के लगभग 10 लाख लोगों पर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवलाय में खास विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुनिश्चित किया जाए कि इस योजना का उपयोग लाभार्थी काईधारकों को शत-प्रतिशत मिले।

मुख्यमंत्री अन्योदय निःशुल्क गैस रफिल योजना लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिए कि राष्ट्रीय खास सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण सभी लाभार्थियों का डेटा अद्यतन किया जाए। वरिष्ठ नगरिकों व अन्य पात्र लोग बायोमेट्रिक कठिनाईयों के कारण राशन से वंचित न रहें, ऐसे सभी मामलों में ऑफलाइन प्रमाणिकरण या वैकल्पिक प्रणाली से राशन वितरण सुनिश्चित किया जाए। खाद्यान्न भंडारण की वर्तमान क्षमता और योजनाओं की भौतिक स्थिति को समीक्षा कर संशोधन

और सुनिश्चित भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि वन राशन वन राशन का प्रभावी रूप से लागू किया जाए ताकि किसी भी स्थान से राशन प्राप्त करने में कोई बाधा न हो।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूर्ण पोर्टल पर रिलय टाइम ड्राइवेशन डेटा की निगरानी सुनिश्चित की जाए। आधार सौंरिग एवं मोबाइल ओटीपी आधारित वितरण प्रणाली को सशक्त बनाया जाए। फजी राशन काई को पहचान करने संबंधी पर कार्यवाई की जाए। लाभार्थियों व खास अधिनियमिता सततने वाले डीलरों

और अधिकारियों को तत्काल निर्देशित किया जाए। हर माह समय पर सभी कार्यालयों को संपूर्ण राशन उपलब्ध कराना जारी रखें एवं पंचायत क्षेत्रों में पूर्व-स्टॉक को तैयार व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। एडव-डेली पैर ऑनगैरुड कैंडों का समयबद्ध ढंग से खानान की आपूर्ति सुनिश्चित हो।

बैठक में अवस्थाना अनुष्ठान परिरप उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आरंन बर्दन, प्रमुख सचिव आरंन सुषोभा, एल. फेनू, आर. मीनाक्षी सुरेश, सचिव चंदेश कुमार यादव, उपर सचिव बंशीधर तिवारी व खास विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को नहीं मिल रहा जीत का प्रमाणपत्र
देहरादून। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कर्न माहारा ने जिला पंचायत चुनाव में विजयी हुए पार्षद समर्थित वोटदाता उम्मीदवारों को जीत का प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने का आरोप लगाया है। माहारा ने कहा उन्होंने पहले ही यह आशंका व्यक्त की थी कि जैसे ही भाजपा को आधार संग्राम कि कांग्रेस के जितने पंचायत अध्यक्ष बनने का रहे हैं, जब गहड़ियां खुलू हो जाएंगी। उन्होंने कहा उनके पास दो जगह से ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर पार्टी समर्थित वोटदाता उम्मीदवारों को जीत का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। माहारा ने कहा डीजलवाला के माहारी से सुप्रसिद्धि कौर ने पंचायत चुनाव में जीत हासिल की है, वह करीब 800 मर्तों से आगे चल रही है, मगर, उन्हें जीत का प्रमाण पत्र प्रशासन की ओर से नहीं दिया जा रहा है। वहीं, दूसरा मामला बागेश्वर का है, यहां पर कांग्रेस पार्टी से प्रमाण पत्र महिला उम्मीदवार सरोज आर्य ने अपनी जीत दर्ज कराई है, मगर वहां पर भी उन्हें जीत का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। वह अभी भी जीत का प्रमाण पत्र मिलने का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और निवाजन आयोग बेंदगांधी पर उत्तर गया है कि इसके विरुध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रोड़वाला में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। माहारा का कहना है कि उन्हें इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों उम्मीदवारों को इतनी जल्दी जीत का प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा।

मालेगांव विस्फोट फैसला, भगवा आतंकवाद की झूठी थ्योरी गढ़ने वालों पर तमाचा : भट्ट

कहा - सनातन धर्म के खिलाफ पाप के लिए कांग्रेस को माफ़ी मांगनी होगी
मुख्य संवाददाता शाह टाइम्स
देहरादून। भाजपा ने मालेगांव विस्फोट पर न्यायालय के निर्णय को भाजपा आतंकवाद की झूठी थ्योरी गढ़ने वालों के मुंह पर तमाचा लगाया है। प्रदेशाध्यक्ष एवं कांग्रेसवा सांसद महेन्द्र पट्ट ने सभी आरोपियों को देशद्रोह बताते हुए निर्दोष सिद्ध होने को शरतमेय जयदेवी की सजीव अभिप्रायिका कहा। कांग्रेस को सनातन धर्म के खिलाफ किए अपने इस पाप के लिए सार्वजनिक माफ़ी मांगनी होगी।

महिंदा को दी प्रतिक्रिया में उन्होंने, 17 वर्ष की लंबी कानूनी हजारी वर्षों के गौरवमय इतिहास पर लागू होने की कोशिश की गई थी। उसका इस पैतृसामिक निर्णय से पूरी तरह खंडित हो गया है। उन्होंने कांग्रेस पर शराना सभी आरोपों का कहा कि, ये उन सनातन, आस्थावादी, सौंद और राष्ट्रसेवा के मान-समर्थन को पुरस्कार देने करने वाला है, जिसकी छत्र के अधिन आतंकवाद-वैसी झूठी थ्योरी के माध्यम से कौंसिल द्वारा कार्रवाई करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि एक बार पुनः न्यायालय के माध्यम से साबित हुआ है कि भाजपा आतंकवाद संभव नहीं और हिन्दू कर्मों की आतंककारी नहीं हैं। निर्दोष कांग्रेस के भारत विरोधी, न्याय विरोधी और सनातन विरोधी चरित्र को पुनः उजागर करता है।



हजारी वर्षों के गौरवमय इतिहास पर लागू होने की कोशिश की गई थी। उसका इस पैतृसामिक निर्णय से पूरी तरह खंडित हो गया है। उन्होंने कांग्रेस पर शराना सभी आरोपों का कहा कि, ये उन सनातन, आस्थावादी, सौंद और राष्ट्रसेवा के मान-समर्थन को पुरस्कार देने करने वाला है, जिसकी छत्र के अधिन आतंकवाद-वैसी झूठी थ्योरी के माध्यम से कौंसिल द्वारा कार्रवाई करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि एक बार पुनः न्यायालय के माध्यम से साबित हुआ है कि भाजपा आतंकवाद संभव नहीं और हिन्दू कर्मों की आतंककारी नहीं हैं। निर्दोष कांग्रेस के भारत विरोधी, न्याय विरोधी और सनातन विरोधी चरित्र को पुनः उजागर करता है।

कैबिनेट मंत्री डॉ. रावत 'भारत युवा पुरस्कार' से सम्मानित

दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में तेलंगाना के राज्यपाल ने किया सम्मानित



मुख्य संवाददाता शाह टाइम्स
नई दिल्ली-देहरादून। सूचे के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत को जयसेवा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में नवाचारी प्रयोगों के लिये देश के प्रतिष्ठित 'भारत युवा पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है। तेलंगाना के राज्यपाल विष्णुगुप्त वर्मा ने प्रतिष्ठित विभागत और गौरव अवार्ड फाउंडेशन को और उस स्थानित युवा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जिसमें प्रदेश के युवा कैबिनेट मंत्री डॉ.

डॉ. रावत ने इस महत्वपूर्ण बताते हुये कहा कि यह सम्मान उच्च जयसेवा के लिये और प्रेरित करेगा।

नई दिल्ली में आयोजित एक ध्वज समारोह में भारत गौरव अवार्ड फाउंडेशन ने राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, सांस्कृतिक चेतना और सूचनात्मक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 21 प्रतिभाशाली व्यक्तियों को पंचवर्ष 'भारत युवा पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। जिसमें प्रदेश के युवा कैबिनेट मंत्री डॉ.

कहा - यह मेरे जीवन का अत्यंत भावुक और प्रेरणास्पद क्षण
भारत युवा पुरस्कार से सम्मानित होने पर सूचे के कैबिनेट मंत्री डॉ. रावत ने कहा कि यह मेरे जीवन का अत्यंत भावुक और प्रेरणास्पद क्षण है। यह सम्मान मुझे सकारात्मक सोच, निरंतर प्रयास और समाज सेवा के प्रति नई ऊर्जा प्रदान करता ताकि मैं देश और समाज के निर्माण में सार्थक योगदान दे सकूँ। उन्होंने भारत गौरव अवार्ड फाउंडेशन का आभार व्यक्त करते हुये कहा कि यह संस्था देश के अनेक युवाओं को नई पहचान और प्रोत्साहन देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। डॉ. रावत ने कहा कि भारत युवा पुरस्कार केवल व्यक्तित्व उपलब्धि नहीं है बल्कि यह युवा वर्ग के सामा, कौशल योगदान को भी पुष्ट करता है। ऐसे सम्मान युवाओं को सुजगरित, कर्तव्यनिष्ठ और समाज हित में सक्रिय करने की प्रेरणा देते हैं।

भन सिंह रावत भी शामिल हैं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. रावत ने कहा कि उत्तराखंड में जनतु हेतु अन्योन्य भवने की दिशा में वह निरंतर, उच्च स्तरीय शिक्षा प्रणाली और का रहे हैं।

पंचायतों में मिली जीत धामी के विकास के विजन पर जनता की मुहर: चौहान

कहा -पार्टी समर्थित प्रत्याशियों की जीत से जन जन में उत्साह

मुख्य संवाददाता शाह टाइम्स
देहरादून। भाजपा ने पंचायत चुनाव के नतीजों को ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रिपल इंजन सरकार का स्पष्ट संकेत बताया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा के प्रत्याशियों और समर्थित कार्यकर्ताओं ने जीत हासिल की उससे जन जन में उत्साह है और यह सौंपा सुख सिंह धामी के विकास के विजन पर मुहर है। उन्होंने कहा कि अन्य निर्दलीय विपक्षी प्रत्याशियों को भी जनता ने अपना मत विकास के लिए दिया है और ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों का

बातचीत करते हुये प्रदेश मीडिया प्रचारि मंचवी चौहान ने बताया कि पार्टी के सभी समर्थित जिला पंचायत समित्य, क्षेत्र पंचायत और प्रान, वार्ड मंच पर निर्वाचित सभी पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत आम जन में उत्साह है और यह सौंपा सुख सिंह धामी के विकास के विजन पर मुहर है। उन्होंने कहा कि अन्य निर्दलीय विपक्षी प्रत्याशियों को भी जनता ने अपना मत विकास के लिए दिया है और ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों का

आगे बढ़ने का समर्थन दायित्व है। चौहान ने कहा कि प्रदेश के अधिकांश ग्राम प्रान और वार्ड जीत कर रहे हैं। जनता के कारकावर्ती ने जीत हासिल की है। जनता ने भाजपा प्रत्याशियों को बड़े पैमाने पर क्षेत्र पंचायत सदस्य की जिम्मेदारी दी है और उसके महेश्वर 89 ब्लॉक में से अधिकांश में भाजपा का स्पष्ट बोंड बनना वश है। जिला पंचायत सदस्य के लिए भी पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों ने लक्ष्य के अनुसार जीत दर्ज कर रहे हैं।

टनकपुर - बागेश्वर रेल लाइन पर केंद्र में सहाजी राज्य की सहमति

राज्य की सहमति के बाद जल्द शुरू होगा रेल लाइन पर काम

शाह टाइम्स व्यूरो
देहरादून। टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन पर जल्द काम शुरू हो सकता है। केंद्र सरकार ने इस परियोजना पर काम शुरू करने के लिए राज्य सरकार से औपचारिक तौर पर सहमत होने का कहा है। राज्य सरकार जल्द इस परियोजना में औपचारिक पत्र केंद्र सरकार को भेजना जा रही है।

प्रस्तावित टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन को कुमाऊ क्षेत्र में रेल नेटवर्क विस्तार की दिशा में गेम चेंजर प्रोजेक्ट के रूप में देखा रहा है। करीब 170 किलोमीटर इस परियोजना के लिए फायनल सर्वे का काम पूरा हो चुका है। इस अगले चरण में परियोजना पर राज्य सरकार से विचार विमर्श होगा। काम शुरू करने से पहले केंद्र सरकार ने राज्य से औपचारिक सहमति

प्रदान करने का कहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को इस दिशा में शीघ्र औपचारिकताएं पूरी करते हुये कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इस तरह टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन का धारांतर पर उत्तर के रास्ता साफ हो रहा है।

कर्णप्रयाग रेल लाइन 2026 तक तैयार होगी

देहरादून। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में रेल नेटवर्क विस्तार करने पर तेजी से काम हो रहा है। इसी क्रम में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेललाइन पर युद्धस्तर पर काम चल रहा है, सामरिक मसल को इस परियोजना का काम 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसी तरह टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन बन जाने के बाद, कर्णप्रयाग-बागेश्वर जैसे दो पर्वतीय शहरों की रेल नेटवर्क से जोड़कर, गढ़वाल-कुमाऊ के बीच रेल सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। साथ ही प्रदेश सरकार के अनुसंधान पर केंद्र सरकार ऋषिकेश-उत्तराखंड और देहरादून-सहारनपुर रेलवे लाइन को डीडीएन भी तैयार कर रही है। 81 किलोमीटर दूरी के तहत न-सहारनपुर शाहपूर रेलवे लाईन के पहले से होकर गुजरेगी। यह रेल लाइन सहारनपुर से देहरादून के हरदोवा रेलवे स्टेशन तक बिछेगी। इसमें 11 किलोमीटर लंबी बार्गेन भी शामिल है।

‘उम्मीद पोर्टल’ पर दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य: बोर्ड

ऊर्जमसिंहनगर, हरिद्वार व देहरादून के वक्फ प्रबंधकों को दिया गया प्रशिक्षण

शाह टाइम्स संवाददाता
देहरादून। वक्फ संसोधन अधिनियम 2025 के तहत वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिये प्रबंधकों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया जा रहा है। राज्य नौशिक्ष अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नगरखंडा देहरादून में देहरादून के वक्फ प्रबंधकों को प्रशिक्षण दिया गया, अभी तक उपस्थित नगर, देहरादून व हरिद्वार के प्रबंधकों को 'उम्मीद पोर्टल' की बारीकियों से रूबरू कराया गया है।



गुरुवार को बोर्ड अध्यक्ष शतावत मय्य व सौंदो अध्यक्ष सिराज उस्मान ने प्रशिक्षण शिफार का उद्घाटन किया। वक्फ बोर्ड के इसपरिषद मौलम्य अली ने 'उम्मीद पोर्टल' पर आईडी बनाने और दस्तावेज अपलोड करने का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि अब हर वक्फ जायदाद के प्रमाण पत्र 'उम्मीद पोर्टल' पर अपलोड करना अनिवार्य है। अब 2 लाख करोड़ की नैनीताल और अन्य पर्वतीय जनपद के प्रबंधकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

यह दस्तावेज अपलोड करने होंगे
देहरादून। उम्मीद पोर्टल' पर वक्फ संख्या, संपत्ति का आकार, स्थान, उपयोग, राज्य और स्थानीय को स्थिति दर्ज करनी होगी। साथ ही कब्जदारों व विक्रेतारों का विवरण भी दर्ज होगा। वक्फ जायदाद के वक्फकर्ता (नस्नतला) का विवरण, खस-खतौनी, कतना, रकबा, चौकी, कोटी और दाखिल-माखिल की प्रमाणित प्रती की अपलोड करनी होगी। कब्जदारों-विक्रेतारों के साफ चल रहे वार्ड का विवरण भी दर्ज करना होगा।



It is informed to the General Public that my High School Certificate C B S E Board Roll no. 53317374 year 2013-15 and B.A Degree year 2021 Roll no 180690230082 Kumaun University is Lost.

-SAHIL PRABHAKAR
S/o Hiltender Prabhakar
H No. 5, P G M Enclave
Near Khokhrai Mandir
Kashipur, US Nagar (UK).

कोच को पिच देखने का पूरा अधिकार है: गिल

के बजाय तीसरी पीढ़े से पहले के लिए कहेंगे, तो ऐसा हमारा साथ पहले करनी हुई। हम दिन दिन समय से क्रिकेट खेल रहे हैं और जब तक आप उस स्थिति तक पहुँच जायेंगे या नो प्ले हैं, आपको विवट को पास से देखने की इजाजत है। यह कोच और कप्तान का काम है। लॉर्ड्स में तीसरी टेस्ट के बाद दरवाजे की बीच का बाव लोखी बंद कर देंगे, इसके बावजूद गिल ने कहा कि इंग्लैंड और भारत के बीच गिल पर मजबूत बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनकी टीम ने इन घटनाओं की दृष्टि जिस तरह का व्यवहार किया उसका 'कॉल अपफॉर्म' नहीं है। उन्होंने कहा, "मैं रिता बतुतु अच्चा है, लेकिन जब आप मैदान पर होते हैं, तो आप अंतर्गत मैदान की कोशिश करते हैं, और दोनों गेंदें काफी प्रतिस्पर्धी रही हैं।"

जी, ताता। रिटायर्ड क्रिकेटरों के
 चैंपियनशिप और लीग टोर्नामेंट
 में पाकिस्तान फाइनल में पहुंच
 भारत ने बुधवार रात उताव
 मारते हुए पाकिस्तान के साथ
 एक खंडेल में मुना कर दिया था। यह
 चैंपियनशिप में खेलने वाला है।
 भारतीय लॉरेंस ने पाकिस्तान के
 खिलाड़ी को हराया था। मुने नहीं
 खेलेंगे। पाकिस्तान के खिलाड़ी
 हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम
 में प्रवेश पा होने और बार जीते का साथ ही
 सेट के कारण फाइनल में पहुंच गई
 छह टीमों में एक टूर्नामेंट में जीते
 को एक मैच में और जीत में
 बर्बक एक मैच बेतौरी जा।
 मुकल्लाद दुसरे स्पोर्ट्सफाइनल
 में फाइनल साइड अंशों में होगा।
 ताता- हम जो करे दवाकी के फाइनल
 स्पोर्ट्सफाइनल में टैम एसम प्र प्रेप्ट

मौ की को उठाने की प्रबल
लोड़ों में से एक के रूप में
हतेगी। लेकिन होली दुनिया की
नंबर 1 वनडे टीम को लेकर कुछ
ही हल्के में नहीं ले रही हैं और
इन्होंने रैंकिंग में अपने सबसे
करीबी प्रतिद्वंद्वियों इंग्लैंड
दूसरे) और भारत (तीसरे) को
30 सितम्बर से शुरू होने वाले
आठ टीमों के टूर्नामेंट में
ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए
में भावि बाधा के रूप में नामित
करा है।

ई-नीलामी बिक्री सूचना

[illegible]

ट्रम्प के बिगड़ते बोल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पूरी तरह बेलगाम होते दिखाई दे रहे हैं। वे किसके विषय में कब क्या बोल दें कोई नहीं जानता। उनके फैंसले भी बेहद अटपटे दिखाई दे रहे हैं। भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद अब उन्होंने कह दिया है कि भारत और रूस को इकोनॉमी डेड हो चुकी है। आम बोलचाल में डेड इकोनॉमी उस स्थिति को कहते हैं जब किसी देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप हो जाए या बिल्कुल सुस्त पड़ जाए। यह एक तरह से किसी देश के दिवालियापन जैसा हो सकता है, जहां न कोई नौकरी रहती है न लोगों की कमाई बढ़ती है। लोग आर्थिक तंगी में फंस जाते हैं।

अब उन्होंने यह बात किस आकलन को आधार पर कही यह तो वही जानें, लेकिन इससे यह तो पता चलता ही है कि वह भारत को लेकर बेहद ही बेरुखा रुख अपना रहे हैं और यह तब है जब वह भारत को मित्र देशों की श्रेणी में भी रखते दिखाई देते हैं। ट्रम्प को समझना होगा कि हर देश को अपनी सीमाएं हैं अपने हित हैं, उसको उन्हीं के हिसाब से फैंसले लेने होते हैं। जैसकि गुरुवार को उद्योगमंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में कहा भी कि सरकार राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगी। सरकार अपने देश के किसानों, मजदूरों, सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। गोयल ने यह भी कहा कि अब तक अमेरिका के साथ चार दौर की बातचीत हो चुकी है और बातचीत अभी टूटी नहीं है।

लगतता है कि ट्रम्प को इससे कोई मतलब नहीं है वह बेहद जल्दबाजी में हैं और वह ट्रेड को लेकर बेहद आक्रामक मुद्रा में हैं। वह किसी को सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं। उन्हें किसी की लाभ-हानि से कोई लेना-देना नहीं है। उन्हें केवल अमेरिका का हित दिखाई दे रहा है। उनकी तमाम कोशिश है कि अमेरिका को जो व्यापार में तमाम फायदें मिलें, जबकि दूसरे देशों को भी फायदा हो इससे उन्हें कोई सरोकार दिखाई नहीं दे रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प को समझना चाहिए कि उनकी अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत है और इस मजबूती के चलते उनका कोई दायित्व भी गरीब विकासशील देशों के प्रति बनता है। आखिर बड़ा वही कहलाता है, जो अपने छोटे देशों का भी ख्याल रखे, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प व्यापार को लेकर किसी तरह का ख्याल रखने के मूड में नहीं हैं और न ही किसी देश की मजबूरी को समझ रहे हैं और सबसे बड़ी विचित्र बात तो यह है कि वह अपनी इस मंशा को छुपा भी नहीं रहे हैं। भारत के संदर्भ में वह खुलकर कह रहे हैं, क्योंकि भारत रूस से बड़ी संख्या में सैन्य साजो-सामान पेट्रोलियम पदार्थ व गैस की आपूर्ति कर रहा है। इसलिए वह भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं। वह नहीं चाहते कि रूस के साथ कोई व्यापार करे। यह कैसे संभव है। हर देश अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी देश के साथ व्यापार करता है। अगर रूस हमें सस्ते दामों पर तेल व गैस दे रहा है, तो इस पर अमेरिका को क्यों आपत्ति होनी चाहिए, लेकिन आपत्ति हो रही है, बल्कि आपत्ति ही नहीं वह एक तरह से दंड भी देना चाहता है। टैरिफ लगाना यह दंड देने का ही एक तरीका है।

केंद्र सरकार अपने आरवासन पर खरी उतरे

उम्मीद है कि अमेरिकी टैरिफ को लेकर केंद्र सरकार अपने आरवासन पर खरी उतरेंगी, मित्र देश बताने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारतीय आयात पर 1 अगस्त से 25 प्रतिशत शुल्क तथा रूस से तेल आयात करने पर पेनाल्टी लगाने की घोषणा की गई है, इस नई चुनौती को केंद्र सरकार अवसर एवं आत्मनिर्भरता में बदलकर देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं होने देगी, इसको लेकर देश को दिए गए इस आरवासन पर कि किसान, छोटे व मझोले उद्योग और राष्ट्रहित से कोई समझौता नहीं करेगी, इस पर खरी उतरकर दिखाएंगी, भारत गरीबों और मेहनतकश लोगों का देश है, हर हाथ को काम देने के साथ देश को आगे बढ़ाने की नीति बनाकर उस पर सही से अमल होना चाहिए।

—सुश्री मायावती, बसपा सुप्रीमा



जब युद्ध अचानक प्रकट होता है, तो कहीं न कहीं कोई उसे वर्षों से यह फसल उगा रहा होता है धीरे, छुपकर, और गहरी चालों के साथ थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर उठता धुआं, कुछ विश्लेषकों के लिए सिर्फ एक पारंपरिक विवाद है, मगर इस लेख के मेरे लिए यह एक बहुत गहरे भू-राजनीतिक युद्ध की भूमिका है, जिसकी स्क्रिप्ट वाशिंगटन, लंदन और तेल अवीव में लिखी जा रही है। इसमें इस्तेमाल किए गए हथियारों से संकेत स्पष्ट है। यह केवल थाई-कंबोडिया संघर्ष नहीं, यह चीन के खिलाफ छेड़ा जा रहा एक परोक्ष वैश्विक युद्ध का पहला कदम है, जिसमें दक्षिण-पूर्व एशिया, ब्रिक्स और पूरा ग्लोबल साउथ युद्ध के शतरंज पर मोहरे बन चुके हैं।

प्राचीन मंदिर, आधुनिक महायुद्ध
सीमा विवाद का प्रतीक बन चुका है प्रीह विहेयर मंदिर। एक प्राचीन खमेर मंदिर जो डांगरेक पर्वतों पर स्थित है, जिसकी दीवारें चुपचाप सियाम के उत्थान, खमेर साम्राज्य की गरिमा, और औपनिवेशिक सीमा-रेखाओं की क्रूरता की गवाह रही हैं।

थाई अभिजात वर्ग और सैन्य नेतृत्व, इस मंदिर को राज्य-गौरव का प्रतीक मानते हैं, जो 1907 की फ्रांस-सियाम संधि से कटे हुए अतीत को पुनःस्थापित करने का माध्यम बन सकता है। परंतु यह सिर्फ एक मंदिर विवाद नहीं। यह एक अवसर है, उस तीसरे पक्ष के लिए जो हर प्राचीन पीढ़ा को भविष्य के युद्ध का बहाना बनाना बना रहा है।

BRI: रेशमी सपनों की अस्थिर नींव
चीन की Belt and Road Initiative एक 6,000 किमी लंबा महायोग, जो युनान से लेकर सिंगापुर तक दक्षिण-पूर्व एशिया की नसों को जोड़ता है। वर्तमान संघर्ष की बुनियाद में कहीं न कहीं गुंती हुई छाया है।

थाईलैंड का हिस्सा (नॉंग खाई एक्सटेंशन) ध्वष्टाचार में उलझा है, जबकि कंबोडिया और लाओस तेजी से बीआरआई के नक्शे पर चमक रहे हैं। में देख रहा हूँ कि अमेरिका के लिए यह बेहद असहनीय है। वह नहीं चाहता कि बीजिंग सड़कों, रेल और बंदरगाहों के माध्यम से एक आर्थिक-सांस्कृतिक धुरी बना दे, जो पश्चिम के पुराने मार्गों को अप्रसार्गिक कर दे। इसलिए, अराजकता फैलाना, कनेक्टिविटी को जड़ से

अनिरुद्धाचार्य ने अपने बयान को लेकर उपजे विवाद व हंगामे के बाद एक वीडियो जारी कर यह कहा है कि मेरी कुछ बहनें प्रसारित हो रहे वीडियो से आहत हैं। कहना चाहता हूँ कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि लिव इन में रहकर चार जगह मुंह मार के किसी के घर जाएंगी, तो क्या वे किसी रिश्ते को निभा पाएंगी? इसलिए लड़की हो या फिर लड़का दोनों को चरित्रवान होना चाहिए। यह कहकर मुआफी मांग. नी तो क्या उन्होंने अपनी चार जगह मुंह मारने जैसी सड़क छाप भाषा शैली का फिर से इस्तेमाल किया। शायद वे सोच रहे हों कि बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम न होगा? जरा सोचिए कि किरण बेदी व कल्पना चावला के देश में जहां लड़कियां चांद पर पहुंचने की होड़ में लगी हुई हैं। उस देश की महिलाओं को यह अशिक्षित रहकर शिक्षा ग्रहण करने की उम्र में शादी रचाने की सलाह देते हैं।

सियाम की परछाइयां: मंदिर, युद्ध और वैश्विक शतरंज



उखाड़ना, और ASEAN को भीतर से फाड़ डालना अमेरिका की रणनीति बन चुकी है।

कंबोडिया: अगला यूक्रेन?
आशयान के संगठित होते देशों की हलचल से इशारा मिलता है कि जिस तरह यूक्रेन को रूस के खिलाफ एक फॉरवर्ड बेस बनाया गया, उसी तरह कंबोडिया क् जहां चीन ने रणनीतिक रूप से रियाम नौसैनिक अड्डा विकसित किया है क् जिसे पश्चिम च्चीन के खिलाफ एक जालघ में बदलने को कोशिया में है। अमेरिका को थाईलैंड जैसे सहयोगी की जरूरत है क्यों है, पश्चिमी हथियारों तक पहुंच रखता है और वहां एक ऐसा राजा और सैन्य वर्ग है जो प्राचीन गौरव और पश्चिमी पूंजी दोनों का मोह रखता है। इस समीकरण में, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भड़काना, ताइवान को चीन के खिलाफ उकसाना, और थाईलैंड-कंबोडिया युद्ध को बढ़ाना। सब कुछ एक साझा रणनीति के धागों से जुड़ा है।

अभिजात वर्ग और राजा के आदमी: खेल के भीतर खेल

राजा के भरोसेमंद लोग, जो सिर्फ सीमा पर तैनात कमांडर नहीं, बल्कि एक मानसिकता के वाहक हैं, जो थाईलैंड को ग्लोबल साउथ के उदय से काटकर, पश्चिम की गोद में बिठाना चाहते हैं। बैंकॉक का अभिजात वर्ग, जो BRI और BRICS के उदय को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। ये वे लोग हैं जो इतिहास से अधिक लाभ में विश्वास करते हैं और मंदिरों के नाम पर युद्ध बेचते हैं, लेकिन लाभ के लिए शांति खरीदते हैं।

असल में कौन है तीसरा पक्ष?

वह कोई एक सरकार नहीं, वह कोई एक सेना नहीं, वह एक गति है जो अराजकता को रणनीति में बदल देती है। CIA, MI6, NATO, तेल अवीव, लंदन सब मिलकर एक ऐसी भू-राजनी. तिक वॉर मशीन बनाते हैं, जो हर हिस्से में एक नया यूक्रेन बनाने के फिराक में है। मंदिर जो शांति



राजा के भरोसेमंद लोग, जो सिर्फ सीमा पर तैनात कमांडर नहीं, बल्कि एक मानसिकता के वाहक हैं, जो थाईलैंड को ग्लोबल साउथ के उदय से काटकर, पश्चिम की गोद में बिठाना चाहते हैं। बैंकॉक का अभिजात वर्ग, जो BRI और BRICS के उदय को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। ये वे लोग हैं जो इतिहास से अधिक लाभ में विश्वास करते हैं और मंदिरों के नाम पर युद्ध बेचते हैं, लेकिन लाभ के लिए शांति खरीदते हैं।

का प्रतीक थे, युद्ध के बहाने बन गए। सीमाएं जो इतिहास में उकरी गई थीं, आज हथियार बन गईं। लेकिन जिस आप युद्ध समझते हैं, वह किसी और की शांति की योजना है और किसी और की गुलामी की तैयारी। ज्ञात रहे हर क्षेत्रीय युद्ध के पीछे एक वैश्विक ब्लूप्रिंट होता है। हर टकराव के पीछे लाभ का गणित छिपा होता है और हर विरोध में एक ऐसी खामोशी दबी होती है, जो कभी भूगोल से, तो कभी इतिहास से, उभर आती है। (लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्व की राजनीतिक मामलों पर गहरी पकड़ रखते हैं, ये विचार उनके निजी विचार हैं)

अपमान के लिए महिलाएं खुद जिम्मेदार



निर्मल राजी

हमारे देश में अनेकानेक स्वयंभू संत, प्रवचनकर्ता, ज्योतिषी व धर्मगुरु टीवी स्क्रीन की शोभा बढ़ा रहे हैं। ऐसे कई स्वयंभू संत व प्रवचनकर्ता जब कैमरे के सामने प्रकट होते हैं तो उनका साज श्रृंगार, मेकअप उनकी निराली अदाएं सब कुछ देखने लायक होती हैं। ऐसे ही एक कथावाचक व आध्यात्मिक गुरु कहे जाने वाले अनिरुद्धाचार्य का नाम अक्सर किसी न किसी विवाद को लेकर चर्चा में रहता है। रूपहले पदों पर नजर आने का शौक रखने वाले अनिरुद्धाचार्य लाफ्टर शेफ में एक अतिथि के रूप में देखे जा चुके हैं। वे विंग बोस 18 में शो के ग्रैंड प्रीमियर के दौरान अतिथि के रूप में भी शो भाग्यमान हो चुके हैं परन्तु वे अपनी कई टिप्पणियों व अंधविश्वास पूर्ण बातों के लिए विवादों में भी रह चुके हैं। कभी कभी शब्दों को तोड़मरोड़कर पेश करने के लिए भी वे हास्य का पर्याय बन चुके हैं। जैसे उन्होंने बिस्किट को विष-की-कट यानी जहर का पैकेट परिभाषित कर दिया। तो कभी पीजजा में पड़ने वाले चीज यानि पनीर को गोंद कहकर उसका मजाक उड़ाते सुने गए। एक बार उन्होंने यह भी कहा था कि महिलाओं को पीछे की ओर नहीं सोना चाहिए क्योंकि इससे उनके स्तन अशुद्ध हो जाएंगे। एक बार एक टीवी शो के दौरान उन्हें कुछ तार्किक व वैज्ञानिक सोच रखने वाले कुछ शिक्षित लोगों

का सामना करना पड़ा। उस समय टीवी एंकर द्वारा उन्हें उनके प्रवचन का वह अंश याद दिलाया गया जिसमें उन्होंने यह कहा था कि गाय के गिल में से गेहूं चुनचुन कर निकालकर उस गेहूं का पिप्सा आटा खाने से पुत्र रत्न प्राप्त होता है परन्तु पिछले दिनों अपने एक तथाकथित प्रवचन में तो अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं का अपमान करने की सभी सीमाएं पार कर दीं। यही महिलाएं जो ऐसे स्वयंभू संतों व प्रवचनकर्ताओं का प्रवचन शुरू होने से पहले सज संवरकर, अपने सिरों पर भारी कलश रखकर शहर में संतों व प्रवचन कर्ताओं की शोभा यात्रा निकाल. कर नगर में इनके प्रवचन में भीड़ जुटाने के लिए माहौल तैयार करती हैं। यही महिलाएं जो इनके प्रवचन में कभी तालियां बजाकर तो कभी नृत्य कर कभी अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर झूम झूम कर इनके समागम में समां बांधती हैं। यही महिलाएं जो इनके प्रवचन सुनाने अपने पति व अन्य पड़ोसियों को भी साथ लाती हैं। जो इन्हें दान देती हैं, जो रोज सुबह मंदिरों में सबसे पहले पहुंचती हैं। जो महिलाएं श्रद्धा पूर्वक मंदिरों व आश्रमों में सेवा करती हैं। इन्हें महिलाओं व उनकी पुत्रियों को लेकर जिस तरह के विकार पिछले दिनों अनिरुद्धाचार्य के मुख से निकले उसने न केवल आम लोगों को बल्कि स्वयं इनके भक्तों को भी आश्चर्य चकित कर दिया। जो शब्द उन्होंने महिलाओं के लिए इस्तेमाल किए शायद इससे अधिक घटिया शब्दों का चयन हो भी नहीं सकता है। उन्होंने अपने एक प्रवचन के दौरान कुंवारी लड़कियों की शारी की उम्र को लेकर अत्यंत विवादित व आपत्तिजनक बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि लोग विवाह के लिए लड़की लाते हैं पच्चीस साल की। अब 25 साल की लड़की चार जगह मुंह मार चुकी होती है। सभ नहीं पर बहुत और वह पच्चीस साल की जब आती है तो पूरी जवान होकर आती है। जब जवान हो कर



आएंगी तो स्वाभाविक है कि वह अपनी जवानी कहीं न कहीं वह, उसकी जवानी फिसल जाएगी। साथ ही उन्होंने 14 साल की उम्र में लड़की की शादी को जायज ठहराया। गौरतलब है कि भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत इस उम्र में शादी अवैध है। इस बयान के बाद तो गोया पूरे देश में भूचाल सा आ गया। मथुरा में भी महिलाएं व अन्य संगठनों ने इनके विरुद्ध प्रदर्शन किया। उनके पुतले फूँके गए। कई जगह से उनके विरुद्ध महिला संगठनों द्वारा एक आई आर करने की खबरें सुनीं गईं। उधर एक बार फिर इस विवादित बयान को लेकर भी टीआरपी की दौड़ में जुटे मीडिया समूहों को मसाला खबरें बेचने की सामग्री हासिल हो गई। महिलाओं के प्रति ऐसी निष्कृत मानसिकता रखने वाले स्वयंभू संतों की भक्ति में डूबी महिलाएं स्वयं ही जिम्मेदार हैं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

अचानक इतनी फुर्ती में क्यों है डीजीसीए

जब भी कभी कोई विमान हादसा होता है या होते-होते टल जाता है तो भारत का नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो ऐसी घटना की जांच करता है। ऐसे मामलों में जांच पूरी होने तक डीजीसीए उस विमान के पायलट व क्रू को ग्राउंड कर देता है यानी उड़ान भरने पर रोक लगा देता है। सवाल है कि क्या डीजीसीए का सिर्फ इतना ही फर्ज है?

सवाल यह भी है कि क्या ऐसी दुर्घटनाओं के बाद की जाने वाली ऐसी जांच में केवल एयरलाइन के स्टाफ की ही गलती क्यों सामने आती है? क्या डीजीसीए के अधिकारियों को हवाई जहाज की नियमित जांच और रख-रखाव की ऑडिट नहीं करनी चाहिए, जो उनका फर्ज है? यदि डीजीसीए द्वारा ऐसे निरीक्षण समय-समय पर होते रहें तो ऐसे हादसे टाले जा सकते हैं। हाल ही में भारत के एविएशन इतिहास में सबसे बड़ा हादसा अहमदाबाद में हुआ।

उसके बाद से ही तमाम जानकारियां सामने आने लगी कि एयर इंडिया के इस विमान हादसे में किसकी गलती हो सकती है। क्या पायलट दोषी हैं? क्या विमान बनाने वाली कंपनी दोषी है? क्या एयर इंडिया के विमान की रख-रखाव करने वाली एजेंसी दोषी है? इन सभी सवालों पर फिलहाल अटकलें ही लगाई जा रही हैं क्योंकि विमान हादसे की जांच अभी चल रही है, लेकिन कहीं पर भी आपको यह सुनने को नहीं मिलेगा कि क्या भारत का नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए अपना काम जिम्मेदारी से कर रहा था? यदि



हां तो फिर ऐसा हादसा कैसे हो गया? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

एयर इंडिया के बोइंग विमानों में अचानक एक के बाद एक हादसों का होना एक गंभीर मुद्दा अवश्य है, लेकिन जिस तरह इन हादसों के बाद डीजीसीए अचानक हरकत में आया है वह कई सवाल उठाता है। क्या डीजीसीए द्वारा नियमित रूप से की जाने वाली ऑडिट में कहीं चूक हुई थी? गौरतलब है कि हर विमान, चाहे वो किसी भी एयरलाइन का क्यों ना हो, उसकी नियमित जांच व रख-रखाव करना अनिवार्य होता है। हर उड़ान से पहले विमान का पूरा निरीक्षण किया जाता है। ऐसे निरीक्षण को परले टेक्नीशियन और उसके बाद इंजीनियर द्वारा किया जाता है।

विमान जो भी कमी पाई जाता है उसे विमान की लॉगबुक में दर्ज किया जाता है। इसके साथ ही विमान में पाई गई कमी को दुरुस्त करने की एंट्री भी इसी

लॉगबुक में की जाती है जिसे विमान से संबंधित सभी लोग साइन भी करते हैं। इसमें पायलट, टेक्नीशियन और इंजीनियर शामिल हैं। इतना ही नहीं इस सबके ऊपर इन लॉगबुक्स का डीजीसीए द्वारा नियमित रूप से ऑडिट भी किया जाता है। यदि इसमें कोई कमी होती है तो डीजीसीए द्वारा संबंधित एयरलाइन को नोटिस दिया जाता है।

वहीं यदि किन्हीं कारणों से डीजीसीए द्वारा ऑडिट को केवल औपचारिकता के लिए किया जाए तो अनदेखी के चलते विमान हादसा कभी भी हो सकता है। ऐसा देखा गया है कि जब भी कभी कोई बड़ा विमान हादसा होता है तो डीजीसीए तुरंत हरकत में आकर कड़े ऑडिट करने शुरू कर देता है। इन ऑडिटों में डीजीसीए यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह किसी भी तरह की लापरवाही के प्रति शून्य सहनशीलता (जीरो टॉलरेंस) रखता है, लेकिन क्या

वास्तव में ऐसा सोचना सही है? यदि डीजीसीए के अधिकारी एयरलाइन की न सुनकर, कानून के हिसाब से हर एयरलाइन का नियमित व विस्तृत ऑडिट करते रहें तो डीजीसीए पर उंगलियां नहीं उठेंगी। पर पता नहीं किस लालच या दबाव में ए जांच नहीं होती।

एविएशन के जानकारों के अनुसार विमान के इंजन में होने वाली कोई खराबी का कारण नियमित रख-रखाव का न होना है। इसके अलावा विमान के स्पेयर पार्ट की गुणवत्ता और पायलट की उचित ट्रेनिंग का न होना भी है। इन घटनाओं के पीछे डीजीसीए के अधिकारियों द्वारा ऐसी कमियों को अनदेखा करना भी एक प्रमुख कारण है। यदि डीजीसीए के अधिकारी केवल इस बात पर जोर न दें कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा तो शायद ऐसी घटनाएं न हों। पिछले दिनों संसद में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री ने यह बताया कि डीजीसीए के स्वीकृत 1644 पदों में से 823 रिक्त हैं। यानी 50 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त हैं। इनमें से अधिकतर पद तकनीकी हैं। यह वही तकनीकी पद हैं जो विमानों की तकनीकी जांच करने में सक्षम होने चाहिए परंतु डीजीसीए के पास यदि टेक्निकल मैनेपावर की कमी है तो वो टेक्निकल ऑडिट किस हद तक कर पाएगा इसका अनुमान कोई भी लगा सकता है। वहीं डीजीसीए के कुछ अधिकारी कुछ चुनिंदा एयरलाइंस, फिर वो चाहे शेड्यूल्ड एयरलाइन हों या नॉन-शेड्यूल्ड एयरलाइन (फ्राइवेंट चार्टर कंपनी) हों, के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है। ऐसे संबंधों का यह नतीजा होता है कि यदि अच्छे संबंधों वाली



रजनीश कपूर

एयरलाइन बड़ी से बड़ी गलती क्यों न करे उसे केवल एक चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है और किसी को कानों कान भी खबर नहीं होती। वहीं किसी अन्य एयरलाइन द्वारा कोई मामूली सी गलती भी हो जाए तो उसके खिलाफ कड़े से कड़े नियमों के तहत कार्यवाही की जाती है। क्या डीजीसीए बताएगा कि ऐसे दोहरे मापदंड क्यों अपनाए जाते हैं?

एक अनुमान के तहत आनेवाले दो दशकों में भारत का नागर विमानन ट्रैफिक 5 गुना बढ़ने की संभावना है। यदि कनाडा और न्यूजीलैंड की तरह हमें भी एविएशन के क्षेत्र में एक अच्छी पहचान बनानी है तो डीजीसीए के अधिकारियों को अपने स्वाधों को दरकिनार करते हुए यात्रियों की सुरक्षा और एयरलाइन कम्पनी के विमानों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। डीजीसीए के एयर सेफ्टी डिपार्टमेंट, फ्लाइट स्टैंडर्ड्स डिपार्टमेंट, एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग व एयरवर्थिनेस डिपार्टमेंट जैसे विभागों को विमानों की जांच के हर पहलू को कड़ाई से लागू करने को गम्भीरता से लेना होगा।

ऐसा करने से एक ओर हवाई यात्रा करने वाले यात्री अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे। वहीं दूसरी ओर एयरलाइन कम्पनियों को भी इस बात का खौफ बना रहेगा कि छोटी सी भूल के चलते उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी हो सकती है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

तिलमिलाए ट्रम्प ने छह भारतीय कंपनियों पर लगाया बैन

कहा: ईरान से चोरी-छिपे कारोबार किया, ईरान बोला: अमेरिका इकोनॉमी को हथियार की तरह कर रहा इस्तेमाल

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान से प्रतिबंधित रसायन और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की खरीद करने वाली 24 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। इनमें 6 भारतीय कंपनियाँ भी हैं। इसके अलावा चीन की 7, यूएई की 6, हान्गकांग की 3, तुर्किये और रूस की 1-1 कंपनी शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इन प्रतिबंधों की घोषणा की।

मंत्रालय का कहना है कि इन कंपनियों ने 2024 में ईरानी मूल के 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा के उत्पाद यूएई के रास्ते मंगवाए। ईरान इस पैसे से न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ा रहा है और आतंकी फंडिंग कर रहा है। ईरान पर 2018 से प्रतिबंध है। ईरान के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार है। देश की इकोनॉमी आयल पर काफी ज्यादा निर्भर करती है। ईरान ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका अपनी इकोनॉमी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। दूतावास ने कहा कि अमेरिका, ईरान और भारत जैसे आजाद देशों पर प्रतिबंध लगाकर उनकी प्रगति और विकास को रोकने की कोशिश कर रहा है। ये प्रतिबंध



कंपनियों ने 2024 में ईरानी मूल के 1000 करोड़ से ज्यादा उत्पाद यूएई के रास्ते मंगवाए

अंतर्राष्ट्रीय कानून और देशों की संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं। यह एक तरह का आधुनिक आर्थिक साम्राज्यवाद है। इन नीतियों का विरोध करना मजबूत ग्लोबल साउथ के लिए खड़ा होना है। किन भारतीय कंपनियों पर कार्रवाई हुई—अलके. मिकल साल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड—इस पर सबसे बड़ा आरोप है। कंपनी ने जनवरी से दिसम्बर 2024 के बीच 84 मिलियन डालर (करीब 700 करोड़ रुपये) से

हो सकता है, भारत को तेल बेचे पाक: ट्रम्प

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पाकिस्तान के साथ आयल डील होने का ऐलान किया है। इसके तहत पाकिस्तान को तेल भंडारों का विकास करेंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान भविष्य में भारत को तेल बेच सकता है। सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए ट्रम्प ने लिखा कि हमने पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल की है, जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर वहाँ के विशाल तेल भंडारों का विकास करेंगे। एक तेल कंपनी को इस साझेदारी के लिए चुना जाएगा। शायद एक दिन वे भारत को भी तेल बेचें। ट्रम्प का यह बयान ऐसे समय आया है, जब कुछ ही घंटे पहले उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। पाकिस्तान की समुद्री सीमा में पिछले साल सितम्बर में तेल और गैस का एक बड़ा भंडार मिला था। पाकिस्तानी मीडिया हाउस डान के मुताबिक, इलाके में एक सहयोगी देश के साथ मिलकर 3 साल तक सर्वे किया गया था। इसमें बाद तेल और गैस रिजर्व की मौजूदगी की पुष्टि हुई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह भंडार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल और गैस का भंडार होगा। फिलहाल वेनेजुएला में तेल का सबसे बड़ा रिजर्व है, जहाँ 34 लाख बैरल तेल है। वहीं, अमेरिका का सबसे शुद्ध तेल का भंडार है, जिसे अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया।

ज्यादा के ईरानी पेट्रोकेमिकल उत्पाद आयात किए। ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड—जुलाई 2024 से जनवरी 2025 तक कंपनी ने 51 मिलियन डालर (करीब 425 करोड़ रुपये) से ज्यादा के ईरानी मेथनाल सहित अन्य उत्पाद खरीदे। ज्युपिटर ड्राई केम प्राइवेट लिमिटेड—इसी अवधि में इस कंपनी ने टॉल्यून समेत ईरानी उत्पादों का करीब 49 मिलियन डालर का आयात किया।

रमणिकलाल एस. गोसालिया एंड कंपनी—इसने करीब 22 मिलियन डालर के पेट्रोकेमिकल्स खरीदे, जिनमें मेथनाल और टॉल्यूइन शामिल हैं। पर्सिस्टेंट पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड—अक्टूबर से दिसम्बर 2024 के बीच कंपनी ने 14 मिलियन डालर का ईरानी मेथनाल आयात किया। कंचन पालिमर्स—इस पर 1.3 मिलियन डालर के ईरानी पालीइथिलीन उत्पाद खरीदने का आरोप है।



नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी बहन व पार्टी सांसद प्रियंका गांधी वाड़ा से बातचीत करते हुए।

सिडनी में लीजियोनेयर्स रोग से एक की मौत, कई बीमार

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहरों में से एक सिडनी के उपनगर पॉट्स पॉइंट में लीजियोनेयर्स रोग से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक अन्य का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सिडनी स्थानीय स्वास्थ्य जिला (एसईएसएलएचडी) ने गुरुवार को बताया कि सिडनी हार्बर ब्रिज और सिडनी ओपेरा हाउस से दो किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित इस उपनगर के सात लोग मई से लीजियोनेयर्स रोग से संक्रमित हो चुके हैं जिनमें एक बुजुर्ग (80) भी शामिल है। बुजुर्ग व्यक्ति जून के अंत में बीमार हुआ था और उसकी मृत्यु हो गई है। शेष छह लोगों को इलाज के

लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पांच लोगों को छुट्टी दे दी गई है और एक व्यक्ति ठीक हो रहा है। एसईएसएलएचडी ने कहा कि 45 से 95 वर्ष की आयु के सभी मरीज एक-दूसरे को नहीं जानते थे लेकिन हो सकता है कि वे क्षेत्र में संक्रमण के एक सामान्य स्रोत के संपर्क में आए हों। लीजियोनेयर्स रोग एक गंभीर प्रकार का निमोनिया है जो लीजियोनेला नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह रोग पानी या मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया को सांस के जरिए अंदर लेने से फैलता है, खासकर उन लोगों को जो कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले हैं या घूमपान करते हैं।

संक्षिप्त समाचार

यूक्रेन पर रूसी हमलों में छह मरे, 52 घायल कीवा। यूक्रेन की राजधानी कीव पर गुरुवार तड़के रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों में कम से कम छह लोग मारे गए और अन्य 52 घायल हो गए। कीव शहर सैन्य प्रशासन के प्रमुख तेमूर तकाचेंको ने टेलीग्राम पर यह जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ितों में एक छह साल का बच्चा भी शामिल है। शहर में 27 जगहों पर हमला हुआ। हमले वाली जगहों पर बचाव अभियान जारी है और पीड़ितों की संख्या बढ़ सकती है।

नेपाल में मानसून जनित आपदाओं में 43 लोगों की मौत काठमांडू। नेपाल में इस साल मानसून का मौसम शुरू होने के बाद से बारिश के कारण आई आपदाओं में 43 लोगों की जान जा चुकी है और 116 अन्य घायल हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बुधवार शाम एक रिपोर्ट में कहा कि मानसूनी बारिश से आई 569 आपदाओं के चलते 16 लोग अभी भी लापता हैं। बाढ़ के कारण 15 लोगों की जान गई और सात घायल हुए। बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत हुई और 95 घायल जबकि भूस्खलन से 14 लोगों की मौत हुई है।

चीन नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे जापान: बीजिंग

बीजिंग/टोक्यो। चीन ने टोक्यो में दो चीनी नागरिकों की गंभीर रूप से पीटाई की रिपोर्टों पर जापानी पक्ष से चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय लागू करने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि आज सुबह टोक्यो में चार लोगों ने दो चीनी नागरिकों पर हमला किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने बीजिंग में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चीन ने इन रिपोर्टों पर ध्यान दिया है।

चीन नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे जापान: बीजिंग

बीजिंग/टोक्यो। चीन ने टोक्यो में दो चीनी नागरिकों की गंभीर रूप से पीटाई की रिपोर्टों पर जापानी पक्ष से चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय लागू करने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि आज सुबह टोक्यो में चार लोगों ने दो चीनी नागरिकों पर हमला किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने बीजिंग में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चीन ने इन रिपोर्टों पर ध्यान दिया है।

पकड़े गए सैनिकों को थाईलैंड रिहा करे: कंबोडिया

नोम पेन्ह/बैकांक। कंबोडिया ने थाईलैंड से युद्धविराम लागू होने के बाद पकड़े गए 20 कंबोडियाई सैनिकों को रिहा करने का आग्रह किया है। कंबोडियाई रक्षा मंत्रालय अवर सचिव और प्रवक्ता, लेफ्टिनेंट जनरल माली सोचेता ने बुधवार को कहा कि उनके 21 सैनिक, थाईलैंड सेना के कब्जे में थे। इसमें से एक मृत सैनिक का शव मिल गया है।

इमरान खान की पार्टी के 166 सदस्यों को 10 साल जेल

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी, पाकिस्तान तहरिक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के 166 नेताओं और कार्यकर्ताओं को 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई।

यह सजा 9 मई, 2023 को पंजाब प्रांत में आईएसआई बिल्डिंग और अन्य सैन्य ठिकानों पर हमले के मामले में दी गई है। सजा पाने वालों में नेशनल असेंबली और सीनेट में विपक्ष के नेता और कई सांसद शामिल हैं। यह फैसला उस समय आया है जब पीटीआई 5 अगस्त से पूरे देश में इमरान खान को रिहा करो आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रही थी। पीटीआई ने फैसलाबाद की आंदोलन निरोधी अदालत (एटीएस) के इस फैसले की कड़ी निंदा की है। पार्टी का

दो साल पहले ISI बिल्डिंग पर हमले मामले में अदालत ने सुनाया फैसला

कहना है कि यह फैसला उनके सांसदों को संसद से अयोग्य घोषित करने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को रोकने की साजिश का हिस्सा है। 9 मई, 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में पीटीआई कार्यकर्ताओं ने फैसलाबाद में आईएसआई बिल्डिंग, लाहौर में जिन्ना हाउस (कोर कमांडर हाउस), मियावाली एयरबेस और रावलपिंडी में सेना मुख्यालय (जीएआईक्यू) सहित कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। फैसलाबाद की एटीसी ने आईएसआई बिल्डिंग हमले के मामले में 185 में से 108 लोगों को दोषी ठहराया और 77 को बरी कर दिया।

कनाडा भी देगा फलस्तीन को मान्यता, ट्रम्प को चढ़ा गुस्सा

प्रधानमंत्री कॉर्नी ने किया ऐलान, सितम्बर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में औपचारिक घोषणा होगी

ओटावा। कनाडा भी फ्रांस और ब्रिटेन की तरह फलस्तीन को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के तौर पर मान्यता देगा। प्रधानमंत्री मार्क कॉर्नी ने बुधवार को इसका ऐलान किया। यह मान्यता औपचारिक रूप से सितम्बर 2025 में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनएचए) के दौरान दी जाएगी। इसके साथ ही कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन के बाद तीसरा देश बन गया है जिसने हाल ही में फलस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया है।

गाजा पट्टी में इजरायल और हमास के बीच करीब दो साल से जंग जारी है। वहां में पानी और खाद्य संकट और रिप्यूजी शिविरों की हमलों से मानवीय संकट गहरा गया है। इसके चलते इजरायल पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। यूएन की इंटीग्रेटेड फूड स्क्रियोरिटी फेज क्लारिफिकेशन की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में अकाल से भी बुरी स्थिति है। प्रधानमंत्री कॉर्नी ने मान्यता के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। इन्हें फलस्तीन को पूरा



इजरायल ने कनाडा के फैसले की निंदा की, ब्रिटेन और फ्रांस पहले ही मान्यता देने का ऐलान कर चुके हैं

फलस्तीन पर कनाडा के फैसले से अमेरिका नाराज

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि फलस्तीन को मान्यता देने के कनाडा के फैसले से उसके साथ व्यापार समझौता करना मुश्किल हो जाएगा। ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्यूब पर कहा कि वह। कनाडा ने अभी घोषणा की है कि वह फलस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने का समर्थन कर रहा है। इससे हमारे लिए उनके साथ व्यापार समझौता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओह कनाडा!!! जुलाई के मध्य में कॉर्नी ने कहा था कि इस बात के 'बहुत कम प्रमाण' हैं कि अमेरिका के साथ आयात शुल्क पर कोई समझौता हो सकता है। पिछले शुक्रवार को ट्रम्प ने इस वार्ता को लेकर निराशा जाहिर की थी। उधर कनाडा ने कहा कि अगर फलस्तीनी प्राधिकरण चुनाव कराने सहित कुछ बदलाव करने के लिए प्रतिबद्ध होता है, तो वह उसे राष्ट्र के रूप में मान्यता दे देगा।

करीब आठ सालों से गाजा में अकाल से भी बुरी स्थिति है। (हमास को अनिवार्य होगा, जो कि 2006 के बाद पहली आतंकी संगठन माना जाता है)। फलस्तीनी बार होगा। चुनाव और शासन में हमास की

गाजा में कुपोषण से सात और लोगों की मौत

गाजा संकट पर चर्चा करने के लिए इजरायल की यात्रा पर जाएंगे अमेरिकी दूत स्टीव वित्कोफ

दुबई। गाजा पट्टी में पिछले 24 घंटों में कुपोषण से सात और लोगों की मौत हो गई है। फलस्तीनी क्षेत्र में हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय ने बताया कि 2023 में इजरायल-हमास युद्ध शुरू होने के बाद से कुपोषण से मरने वालों की कुल संख्या अब 154 हो गई जिसमें 89 बच्चे शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र समर्थित वैश्वक खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों ने मंगलवार को चेतावनी दी कि गाजा में अकाल की सबसे खराब स्थिति वर्तमान में चल रही है। इजरायल ने कहा है कि वह गाजा में आने वाली सहायता पर प्रतिबंध नहीं लगा रहा है, लेकिन उसका ये दावा यूरोप में उसके करीबी सहयोगियों, संयुक्त राष्ट्र और



गाजा में सक्रिय अन्य एजेंसियों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। इस बीच अमेरिका के विशेष दूत स्टीव वित्कोफ गुरुवार को गाजा संकट पर चर्चा करने के लिए इजरायल की यात्रा पर जाएंगे। एक अलग घटनाक्रम में गाजा अस्पताल के सूत्रों ने बीबीसी को बताया कि बुधवार सुबह दक्षिणी गाजा के राफा इलाके में गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन (जीएचएफ) के सहायता वितरण केंद्र के पास छह फलस्तीनी मारे गए। सूत्रों ने बताया कि भीड़ ने वितरण केंद्र के खुलने से कुछ देर पहले ही उसमें

2023 में इजरायल-हमास युद्ध शुरू होने के बाद से कुपोषण से मरने वालों की कुल संख्या अब 154 हो गई है

घुसने की कोशिश की थी और एक इजरायली टैंक ने उन पर हमला कर दिया। जीएचएफ ने आरोपों का खंडन करते हुए बीबीसी को बताया कि उसके केंद्रों पर या उसके आसपास कोई हत्या नहीं हुई। इजरायली रक्षा बल (आईडीएफ) ने भी बीबीसी को बताया कि 'प्रारंभिक समीक्षा से पता चलता है कि हताहतों की संख्या आईडीएफ के पास मौजूद जानकारी से कम नहीं होगी।'

D.A.V. COLLEGE, ARYA SAMAJ ROAD, MUZAFFARNAGAR
SHORT-TERM TENDER NOTICE

Sealed tenders are invited from reputed and experienced Firms/ Suppliers for the supplying of following material for the session 2025-26.

S	Particular of work	Approx Cost (in Lac)	Cost of Tender form	E.M.D.	Completion period
1	Lab Equipments/ Chemical/ Glassware/ Polyware and other consumables	10.00	1,000/-	50,000/-	30 Days from the date of order
2	Furniture	5.00	1,000/-	25,000/-	
3	Library Books	2.00	1,000/-	10,000/-	
4	Printing of College Magazine "VEENAPANI" Session 2024-25	5.00	1,000/-	25,000/-	45 Days from the date of order

NOTE

1. Terms and Conditions are explained in Tender Documents. Description of Items to be purchased mentioned in Tender form.
2. The Tender form can be purchased from **Office Counter No. 03** between 10:30 am to 02:00 pm from 01st August to 7th August - 2025 at the cost of Rs. 1000/- by cash payment.
3. Tenders may be Submitted in **Office Counter No. 03** upto 7th August - 2025 upto 02:00 pm.
4. Tenders will be opened on 12th August 2025 at 02:30 pm in Principal Office.
5. The college reserves all the rights to reject any tender without explaining any reason.

Dated: 30.07.2025

(Dr. Garima Jain)

यौन समस्याएं

यौन समस्याओं के विशेषज्ञ

पुराने से पुराने यौन रोग के मरीज एक बार अवश्य मिलें

डा. सम्राट

नशामुक्ति, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा तम्बाकू, प्रोक्सीवॉन कैप्सूल, अफीम, चरस, डोपे पोस्ट इंजेक्शन व अन्य नशा छुड़ाने का स्थायी ईलाज।

नावल्टी सिनेमा चौक मुजफ्फरनगर (यू.पी.)

M-9412211108

ADMISSION OPEN

Session 2025-26

न्यू स्टेट नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल कालेज

12 किमी. स्टोन, रुड़की रोड, मुजफ्फरनगर

Affiliated by: U.P. State Medical Faculty Lucknow and recognized by the U.P. Govt.

कोर्स

• डीग्री पीएचडी • ऑप्टोमेट्री • ओएचटी टेक्नीशियन

कोर्स अवधि: 2 वर्ष

योग्यता: 12वीं पास बायोलोजी/गणित

हसन नर्सिंग होम

92, उत्तरी सरवट गेट, मुजफ्फरनगर

8899777782

मो: **9897640744**

अखबार की कटिंग साथ लाने वाले को 5000 की छूट